गढ़ा में भव्य झांकियों के साथ निकला दशहरा जुलूस

रामलीला मैदान में किया गया रावण दहन

जबलपुर, (एजेंसी)। गढ़ा गोंडवाना का ऐतिहासिक दशहरा चल समारोह गुरुवार को अपनी परंपरा, भव्यता और धार्मिक वैभव के साथ निकाला गया। श्री रामलीला समिति गढ़ा के नेतृत्व में संकट मोचन मंदिर, गौतम गंज से रात्रि ७ बजे भगवान श्रीराम, लक्ष्मण एवं हनुमान जी के पूजन-अर्चन के साथ चल समारोह का शुभारंभ हुआ। ढोल-नगाड़ों की गूंज, बैंड की धुन, दुलदुल घोड़ी का नृत्य, आकर्षक झांकियों और आतिशबाजी के बीच निकले इस भव्य समारोह में २५ प्रतिमाएं शामिल हुईं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित रामलीला समिति के संचालक अशोक मनोध्याय, दशहरा चल समारोह अध्यक्ष अजय तिवारी धतुरहा, समिति अध्यक्ष एवं निर्देशक राजेश मिश्रा, महामंत्री एडवोकेट अरुण दीक्षित, राकेश पाठक, लोकराम कोरी, मनोज पाटकर एवं संकट मोचन मंदिर समिति के सदस्यों ने भगवान श्रीराम, लक्ष्मण एवं हनुमान जी का पूजन-अर्चन किया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात जय श्रीराम के उद्घोष के साथ शोभायात्रा आगे बढ़ी।

झांकियों ने मोहा मन

श्री रामलीला समिति की ओर से निकाली गई झांकियों में रथ पर विराजमान भगवान शिव, श्रीराम-रावण युद्ध का जीवंत दृश्य, नौ देवियों की झांकी तथा रावण, मेघनाद एवं कुंभकरण के विशाल पुतले विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। आधुनिक विद्युत सज्जा से सुसज्जित झांकियों और आतिशबाजी ने समारोह की भव्यता में चार चांद लगा दिए। मेजर बीटी तिराहे पर विभिन्न झांकियों एवं देवी प्रतिमाओं के एक साथ सम्मिलित होने से चल समारोह ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। ऐतिहासिक शोभायात्रा शुक्ला नगर से प्रारंभ होकर एकता चौक, मेजर बीटी तिराहा, आनंदकुंज, पंडा की मढ़िया, त्रिपुरी तिराहा एवं देवताल होते हुए गढ़ा रामलीला मैदान पहुंची। पूरे मार्ग में जय श्रीराम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। रामलीला मैदान में परंपरानुसार भगवान श्रीराम द्वारा रावण, कुंभकरण एवं मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया।

चल समारोह में मंडल अध्यक्ष प्रणय गुप्ता, पार्षद प्रिया संजय तिवारी, पूजा श्रीराम पटेल, मनीष महेश पटेल, सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष श्याम साहनी, कोषाध्यक्ष गुलशन माखिजा, रमाशंकर कटारे, राजेंद्र प्यासी, हरीश मनोध्याय, नीलेश चौबे, पंकज अवस्थी, देवेंद्र मनोध्याय, मदन गोपाल पटेल, भूपेंद्र उपाध्याय, भोलाराम खत्री, सह-निर्देशक मोती शिवहरे, व्यास माधव दुबे, राकेश मिश्रा, राजेश नेमा, केदार शर्मा, आदि उपस्थित रहे।

सरकारी बीमा योजना में ४८२ फर्जी क्लेम, ९.६० करोड़ का घोटाला

भोपाल, (एजेंसी)। सरकारी बीमा योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। योजना के तहत ४८२ कथित फर्जी क्लेम के जरिए ९.६० करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में बिना मृत्यु हुए ही लोगों को कागजों में मृत दर्शाकर डेथ सर्टिफिकेट के आधार

बिना मरे ही डेथ सर्टिफिकेट से हुआ खेल

पर बीमा राशि हासिल करने का आरोप है। सीआईडी मामले दर्ज कर जांच कर रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर बीमा दावों को मंजूरी दिलाई गई। इस तरह सरकारी योजना की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यदि मृतकों के नाम पर भुगतान किया गया है, तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग और दस्तावेजों में हेराफेरी का गंभीर मामला है।

अब जांच में यह पता लगाना जरूरी होगा कि फर्जी प्रमाणपत्र किसने जारी किए, क्लेम को किस स्तर पर मंजूरी मिली और इस पूरे मामले में कौन-कौन शामिल है। दोषियों की पहचान कर राशि की वसूली तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना जरूरी है।

सरकारी जमीनों पर कब्जे का सिंडिकेट!

भोपाल में सबसे ज्यादा अवैध कब्जों का दावा अवैध कारोबार से मलाई खा रहे कब्जाधारी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में सरकारी जमीनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में १० हजार करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीनों पर अवैध कब्जे होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि कई जगह धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए और धीरे-धीरे वहां पक्के निर्माण तक खड़े कर दिए गए। कुछ मामलों में ट्रस्ट और समितियां बनाकर इन संपत्तियों से आर्थिक गतिविधियां संचालित किए जाने की बात भी सामने आई है। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यह है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे का असर अब केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं रह गया है। प्रमुख सडक़ों के किनारे बने ढांचे, अस्थायी टेंट और आयोजन स्थलों के कारण यातायात प्रभावित होने की शिकायतें हैं। सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर निर्माण होने से लेकर उसके व्यावसायिक इस्तेमाल तक संबंधित विभागों की निगरानी कहां है? यदि जमीन सरकारी है, तो उस पर हुए निर्माण की अनुमति किसने दी और कार्रवाई के बावजूद कब्जे क्यों बने हुए हैं?

शहरों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का स्वरूप धीरे-धीरे बदलने के आरोप हैं। शुरुआत में अस्थायी ढांचा खड़ा किया जाता है, फिर उसके आसपास निर्माण बढ़ता जाता है। कुछ स्थानों पर पक्के भवन बना दिए गए हैं। वहीं, कुछ कब्जों से जुड़े लोगों द्वारा ट्रस्ट या समितियां गठित किए जाने की बात भी कही जा रही है। इन परिस्थितियों में जमीन के वास्तविक स्वामित्व, निर्माण की अनुमति और संपत्ति के इस्तेमाल की जांच जरूरी हो जाती है। किसी धार्मिक स्थल या संस्था का अस्तित्व अपने आप में जमीन पर वैध अधिकार का प्रमाण नहीं है। इसी तरह, किसी ट्रस्ट या समिति का पंजीयन भी सरकारी जमीन पर कब्जे को वैध नहीं बनाता। हालांकि, प्रत्येक मामले में जमीन के रिकॉर्ड, निर्माण की स्थिति और संबंधित दस्तावेजों की अलग-अलग जांच आवश्यक है। जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर अस्थायी अतिक्रमण स्थायी रूप ले लेते हैं। बाद में इन्हें हटाने पर स्थानीय विरोध, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आती हैं। इसी कारण शुरुआत में ही अतिक्रमण रोकना अधिक प्रभावी माना जाता है।

भोपाल में सडक़ किनारे बने ढांचे बन रहे परेशानी

भोपाल में बागसेवनिया थाने से अमलतास चौराहे होते हुए ११ मील बायपास तक सडक़ किनारे बने कुछ ढांचों को लेकर यातायात की समस्या का मुद्दा उठाया गया है। आरोप है कि मुख्य मार्गों के पास धार्मिक ढांचे खड़े होने और विशेष अवसरों पर टेंट-तंबू लगाने से सडक़ पर आवाजाही प्रभावित होती है। स्थिति बिगडऩे पर पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। यदि सडक़ के किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, तो उसका असर केवल संबंधित जमीन तक सीमित नहीं रहता। इससे सडक़ की उपलब्ध चौड़ाई कम हो सकती है, वाहनों की गति प्रभावित होती है और व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनती है। ऐसे मामलों में राजस्व, नगर निगम, पुलिस और संबंधित सडक़ प्राधिकरण के बीच समन्वय की जरूरत होती है। अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक रास्तों का इस्तेमाल प्रभावित हो रहा हो, तो प्रशासनको जमीनकी सीमा और निर्माण की वैधता की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, कार्रवाई केवल छोटे या नए अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पुराने और प्रभावशाली कब्जों की भी समान मानकों पर जांच जरूरी है।

अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल

सेवानिवृत्त सहायक भू-अभिलेख अधिकारी ओपी भट्ट के मुताबिक, जमीन से जुड़े मामलों में स्थानीय अधिकारी कई बार विवाद और विरोध से बचने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि शासन स्तर पर व्यापक अभियान नहीं चलने से अतिक्रमण की समस्या बढ़ती है। वन एवं राजस्व मामलों के जानकार अनिल गर्ग ने भी जिला मुख्यालयों से लेकर पंचायत स्तर तक सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर उदासीनता की बात कही है। उनके अनुसार, बड़े पैमाने पर कब्जे होने के बाद जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराना कठिन हो जाता है। इसके लिए शासन स्तर पर समन्वित अभियान चलाने की आवश्यकता है। इन टिप्पणियों के बीच प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल महत्वपूर्ण है। सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जमीन की प्रकृति के अनुसार नगर निगम, विकास प्राधिकरण या अन्य विभागों की भूमिका भी हो सकती है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि किस जमीन पर कब कब्जा हुआ, संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी कब मिली और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई। यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत के आरोप हैं, तो उनका निर्धारण दस्तावेजी साक्ष्य और निष्पक्ष जांच के आधार पर होना चाहिए। केवल अतिक्रमण मौजूद होने से किसी अधिकारी या संगठन की आपराधिक संलिप्तता स्वत: साबित नहीं होती।

जमीन पर कब्जे के बाद कमाई के रास्ते

अतिक्रमण को लेकर उठ रही शिकायतों में जमीन के आर्थिक इस्तेमाल का पहलू भी शामिल है। आरोप है कि कुछ स्थानों पर धार्मिक आयोजनों के नाम पर चंदा जुटाया जाता है, जबकि कुछ भवनों या परिसरों का विशेष अवसरों पर किराये के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि ऐसा किसी सरकारी जमीन पर बिना वैध अधिकार या अनुमति के हो रहा है, तो यह जांच का विषय है कि उससे होने वाली आय किसके पास जा रही है और संपत्ति का इस्तेमाल किस आधार पर किया जा रहा है।

चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू

उज्जैन से अयोध्या तक ७० दिन की पदयात्रा जीतू पटवारी और साधु-संत हुए शामिल

उज्जैन, (एजेंसी)। मंदिरों में चढ़ावे की कथित चोरी और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू की है। उज्जैन से अयोध्या तक निकाली जा रही इस पदयात्रा में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित साधु-संत भी शामिल हुए। करीब ७० दिन तक चलने वाली इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी अलग-अलग पड़ावों पर शामिल होंगे।

यात्रा का उद्देश्य मंदिरों में चढ़ावे की व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की संपत्ति और सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दों को उठाना है। उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या तक पहुंचने वाली इस पदयात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह विभिन्न धार्मिक स्थलों और क्षेत्रों से गुजरेंगे। यात्रा में साधु-संतों की भागीदारी इसे धार्मिक और राजनीतिक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बना रही है।

मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह की इस पहल को कांग्रेस की धार्मिक मुद्दों पर सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान मंदिरों में चढ़ावे की कथित चोरी और धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए जा रहे है। ७० दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेतृत्व सनातन परंपराओं, धार्मिक आस्था और मंदिरों की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा कि यह यात्रा धार्मिक- सामाजिक विमर्श के साथ प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव डालती है। कंप्यूटर बाबा ने हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की अनुमति नहीं दिए जाने पर कलेक्टर के पास धरना दिया था. उसके बाद जिला प्रशासन को अनुमति देनी पड़ी. अगली कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं. इसलिए इस यात्रा का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है।

युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल

परिजनों ने थाने में पिटायी का लगाया आरोप, न्यायिक जांच होगी

जबलपुर, (एजेंसी)। लार्डगंज थाना अतंर्गत गढ़ा फाटक स्थित महाकाली के दर्शन करने आए शहपुरा से आए एक २७ वर्षीय युवक आकाश चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मामला गरमा गया। परिजनों ने पुलिस पर थाने के भीतर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में छेड़छाड़ करने पर भीड़ ने युवक को पीटा था। पुलिस उसे सुरक्षा की दृष्टि से थाने लेकर आई थी। देर रात तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर नेशनल अस्पताल में परिजनों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की बात कही गई है।

मामा के बेटे के साथ निकला था घूमने

जानकारी के अनुसार, शहपुरा क्षेत्र के ग्राम भभकी निवासी २७ वर्षीय आकाश चौधरी सोमवार रात करीब ९:३० बजे अपने मामा के बेटे २० वर्षीय विवेक चौधरी निवासी पिपरिया, के साथ बाइक से जबलपुर पहुंचा था। दोनों गढ़ाफाटक स्थित महाकाली मंदिर में दर्शन करने गए थे। इसी दौरान भीड़ के बीच आकाश के साथ विवाद होने की बात सामने आई।

वीडियो बनाने के दौरान विवाद, थाने ले गई पुलिस

मृतक के ममेरे भाई विवेक के मुताबिक, मंदिर परिसर में भीड़ के बीच आकाश मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी दौरान एक महिला सब-इंस्पेक्टर से उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस आकाश को लार्डगंज थाने ले गई। विवेक का आरोप है कि जब वह पीछे-पीछे थाने पहुंचा, तो परिसर में खून बिखरा हुआ था और पुलिसकर्मी आकाश के साथ मारपीट कर रहे थे। विवेक के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने उसे घर जाने और सुबह थाने आने के लिए कहा। इसके बाद वह डर के कारण वापस गांव चला गया।

अस्पताल में पुलिस से झूमाझपटी

मंगलवार सुबह गांव के कोटवार भूपत ने परिजनों को आकाश की अस्पताल में मौत होने की सूचना दी। इसके बाद परिजन नेशनल अस्पताल पहुंचे। विवेक के आरोपों के आधार पर परिजनों ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान परिजनों और पुलिसकर्मियों के बीच झूमाझटकी होने की बात भी सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक, गढ़ा फाटक क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना मिली थी। इस दौरान भीड़ ने युवक के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने उसे सुरक्षा की दृष्टि से लार्डगंज थाने पहुंचाया था। पुलिस का कहना है कि युवक थाने में बेंच पर सो गया था। देर रात तबीयत बिगड़ने पर उसे नजदीकी नेशनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब एक से डेढ़ घंटे के उपचार के बाद उसकी मौत हो गई।

न्यायिक जांच होगी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराए जाने की बात कही गई है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर परिसर में विवाद किन परिस्थितियों में हुआ, युवक के साथ मारपीट किसने की और थाने में उसके साथ किसी तरह की मारपीट हुई थी या नहीं। जांच के तहत गढ़ा फाटक क्षेत्र से लेकर लार्डगंज थाने तक के सीसीटीवी फुटेज जुटाकर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों से युवक की मौत के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है।

जबलपुर के बैलेंसिंग राक की अनदेखी क्यों...?

पुरातत्व विभागके दोहरे मापदंड पर सामाजिक संघटनों ने किया प्रदर्शन

जबलपुर, (एजेंसी)। शहर की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले बैलेंसिंग रॉक की उपेक्षा को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पर्यटन विभाग और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मंच का आरोप है कि जब महाबलिपुरम के प्राचीन रॉक को संरक्षण दिया जा सकता है, तो जबलपुर के विश्वप्रसिद्ध बैलेंसिंग रॉक की सुरक्षा और पर्यटन विकास के लिए ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया।

मंच के अनुसार, पुरातत्व विभाग ने महाबलिपुरम मंदिर के समीप स्थित प्राचीन कृष्णा बटर बॉल को मंदिर परिसर के निकट होने और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर संरक्षित किया है। वहीं, जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक भी पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित मदन महल किले की चट्टानों का हिस्सा बताया जाता है और किले से लगभग ४०० मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

चार महीने बाद भी नहीं पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पर्यटन निगम की उदासीनता पर भी नाराजगी जताई। मंच का आरोप है कि क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन शर्मा को जबलपुर में पदस्थ हुए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक बैलेंसिंग रॉक का अधिकृत निरीक्षण तक नहीं किया। पर्यटन स्थल की स्थिति और संभावनाओं का आकलन किए बिना इसके विकास की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने पर सवाल खड़े किए गए।

पर्यटन स्थल की अनदेखी

बैलेंसिंग रॉक की उपेक्षा के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण, रखरखाव और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए संबंधित विभाग तत्काल ठोस कार्ययोजना तैयार करें। उनका कहना था कि यह स्थल जबलपुर की ऐतिहासिक और प्राकृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसकी अनदेखी शहर के पर्यटन हितों के विपरीत है।

प्रदर्शन के दौरान डॉ. पी.जी. नागपांडे, एडवोकेट वेदप्रकाश अधौलिया, डी.के. सिंह, संतोष श्रीवास्तव, सुभाष चंद्रा, डी.आर. लखेरा, अशोक यादव, के.सी. सोनी, यशवंत कोष्टा, श्याम सोलंकी, अशोक नामदेव, विनय दुबे, धर्मेंद्र पांडे और राममिलन शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मंच ने मांग की कि पर्यटन निगम और पुरातत्व विभाग बैलेंसिंग रॉक की स्थिति का निरीक्षण कर संरक्षण एवं विकास के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि इस महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को उपेक्षा से बचाया जा सके।

मप्र में रोज तीन हजार मरीज पहुंच रहे अस्पताल

वायरल फीवर में राहत की गोली, सेहत पर भारी पड़ रही मनमानी

भोपाल, (एजेंसी)। वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम और खांसी के बढ़ते मामलों के बीच दवाओं का खुद इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति चिंता बढ़ा रही है। बुखार और दर्द से जल्द राहत पाने के लिए लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही पेनकिलर और एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इससे बीमारी की सही पहचान में देरी के साथ दवाओं के दुष्प्रभाव का खतरा भी बढ़ रहा है। खासकर दर्द निवारक दवाओं का गलत इस्तेमाल किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एंटीबायोटिक का अनावश्यक सेवन भविष्य में बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज मुश्किल बना सकता है। प्रदेश में वायरल फीवर के करीब तीन हजार मरीज रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं। भोपाल में जेपी, हमीदिया और जिला अस्पतालों के अलावा निजी क्लीनिकों में भी सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इंदौर और जबलपुर में करीब ५००-५००, ग्वालियर में २०० और उज्जैन में १५० मरीज रोज वायरल फीवर से पीडित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।

चिकित्सकों के मुताबिक, ओपीडी में आने वाले कई मरीज पहले ही अपनी मर्जी से दवाएं ले चुके होते हैं। एमबीबीएस, एमडी और एफआईसीसीडी डॉ. समन ताहिर के अनुसार, उनके क्लीनिकल अनुभव में करीब ५० प्रतिशत मरीज डॉक्टर से

ओपीडी में आने से पहले ही दवा खा रहे ८० प्रतिशत मरीज, डाक्टरों ने किडनी पर खतरे को लेकर किया आगाह

मिलने से पहले दवा ले चुके होते हैं। इनमें कई मरीज ऐसे होते हैं, जिन्हें दवा से तत्काल राहत तो मिल जाती है, लेकिन गलत दवा, अनुचित डोज या लंबे समय तक सेवन से नुकसान का जोखिम बना रहता है। डॉ. ताहिर स्पष्ट करते हैं कि यह उनके क्लीनिकल अनुभव पर आधारित आकलन है, किसी बड़े सर्वे का निष्कर्ष नहीं। कौन-सी दवा दी जाए, उसकी कितनी मात्रा हो और कितने समय तक इस्तेमाल किया जाए, यह मरीज की बीमारी, मेडिकल हिस्ट्री और किडनी की स्थिति जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करता है।

सोशल मीडिया की सलाह पड़ सकती है भारी

डॉ. प्रज्ञेश सक्सेना के मुताबिक, पहले उनकी ओपीडी में करीब १० प्रतिशत मरीज ऐसे आते थे, जो डॉक्टर को दिखाने से पहले खुद दवा ले चुके होते थे। अब उनके व्यक्तिगत अनुभव में ऐसे मरीजों का अनुपात करीब ८० प्रतिशत तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि गूगल और सोशल मीडिया से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने का चलन बढ़ा है। कई लोग इंटरनेट पर बताए गए नुस्खों या किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव के आधार पर अपनी दवा और व्यायाम तय कर लेते हैं। कुछ मरीज तो हफ्तों या महीनों तक दर्द की दवा लेते रहते हैं, लेकिन दर्द की असली वजह जानने के लिए जांच नहीं कराते। डॉक्टरों के मुताबिक, एक व्यक्ति के लिए कारगर दवा दूसरे के लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं। उम्र, दूसरी बीमारियां, पहले से चल रही दवाएं और शरीर की स्थिति के अनुसार इलाज बदल सकता है।

दर्द दबता है, बीमारी नहीं

डॉ. समन ताहिर के अनुसार, दर्द के पीछे मांसपेशियों की समस्या, पोषण की कमी या कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। पेनकिलर कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन दर्द की मूल वजह को खत्म नहीं करती। बार-बार या लंबे समय तक कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने से किडनी को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। डॉ. प्रज्ञेश सक्सेना भी दर्द की समस्या में जरूरत के मुताबिक वॉर्किंग, व्यायाम, मांसपेशियों को मजबूत करने और संतुलित खानपान पर जोर देते हैं।

आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में मनमानी, १३,५७१ की जगह मिल रहे ५,५०० रुपये

हर जिले में अलग-अलग भुगतान की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भारी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि एक ही तरह का काम करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग जिलों में अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। निर्धारित १३,५७१ रुपये के मासिक वेतन के बजाय कई कर्मचारियों को महज ५,५०० रुपये का भुगतान किए जाने की शिकायत है। इससे कर्मचारियों मे रोष देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा गड़बड़ियों की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बताई जा रही है। अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के नाम पर कम राशि मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। कर्मचारियों का आरोप है, ठेका एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण निर्धारित वेतन का पूरा लाभ संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है।

एक ही काम,वेतन अलग-अलग

आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में जिलेवार अंतर ने भुगतान व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्धारित वेतन १३,५७१ रुपये है, तो ५,५०० रुपये भुगतान किए जाने पर बाकी राशि कहां जा रही है, इसकी जांच जरूरी है। हालांकि, वास्तविक देय वेतन का निर्धारण संबंधित पद, लागू सरकारी आदेश और वैधानिक कटौतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार सभी जिलों में आउटसोर्स एजेंसियों के भुगतान रिकॉर्ड की जांच कराए। बैंक खातों में जमा वेतन, उपस्थिति रजिस्टर और एजेंसियों को किए गए भुगतान का मिलान किया जाए। दोषी एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये. कर्मचारियों को बकाया राशि दिलाई जाए। सवाल यह है कि कर्मचारियों के शोषण की शिकायतों पर जिम्मेदार विभाग कब कार्रवाई करेगा?

आज प्रदेशभर में सडक़ों पर उतरेंगे कर्मचारी

भोपाल, (एजेंसी)। दीपावली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाने की मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से की है। वर्तमान में कर्मचारियों को ५८ प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत दी जा रही है। जबकि, एक जनवरी २०२६ से भारत सरकार अपने कर्मचारियों को ६० प्रतिशत की दरसे महंगाई भत्ता दे रही है।

पिता को गाली देने पर भड़के बेटे

डंडेसे पीटकर उतारा मौतके घाट, नाबालिग सहित दो आरोपित गिरफ्तार

जबलपुर, (एजेंसी)। खेती-किसानी और मजदूरी को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। पिता को अपशब्द कहे जाने से नाराज दो आरोपियों ने एक व्यक्ति पर डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है।

तिलवारा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा के मुताबिक, सोमवार दोपहर ग्राम नारायणपुर में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल शेर सिंह तेकाम को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उसके भाई मुन्नालाल तेकाम ने पुलिस को बताया कि वह खेती-किसानी करता है। दोपहर करीब १:३० बजे शंभू तेकाम और १७ वर्षीय एक किशोर ने शेर सिंह के साथ लकड़ी के डंडे से मारपीट की थी। हमले में उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। बेहोशी की हालत में उसे १०८ एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

छात्राओं का प्रदर्शन, साफ पानी और सुरक्षा की मांग

कटारा हिल्स के छात्रावास में खाने में कीड़े मिलने का आरोप

भोपाल, (एजेंसी)। कटारा हिल्स स्थित आकांक्षा योजना के तहत संचालित छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता खराब है और खाने में कीड़े मिलने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और वाटर कूलर से जुड़ी समस्याओं के कारण भी उन्हें परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), भोपाल ने छात्रावास की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को भोजन, पानी, साफ-सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं में लापरवाही छात्राओं के स्वास्थ्य और पढ़ाई के माहौल को प्रभावित कर सकती है। छात्राओं की शिकायत है कि छात्रावास में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। खाने में कीड़े मिलने के आरोप को गंभीर बताते हुए उन्होंने इसकी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े। पेयजल व्यवस्था को लेकर भी छात्राओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वाटर कूलर की मरम्मत कराने के साथ स्वच्छ पानी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा छात्रावास में साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओंको भी बेहतर बनाया जाए।

मप्र में फारेंसिक विशेषज्ञों की कमी दूर करेगा गुजरात

प्रदेश में २००३ स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ २४० अधिकारी कार्यरत, नए आपराधिक कानूनों के पालन में आ रही बाधा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी दूर करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में स्वीकृत २००३ पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल २४० फॉरेंसिक अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसे में गंभीर अपराधों की जांच के दौरान घटनास्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इस कमी को दूर करने के लिए अब गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं लेने पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव ने मध्यप्रदेश के अधिकारियों को इस दिशा में पहल करने का सुझाव दिया। इसके बाद पुलिस विभाग ने विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी संसाधन और मानवबल उपलब्ध कराना है।

२००३ पदों पर सिर्फ २४० अधिकारी

प्रदेश में फॉरेंसिक अधिकारियों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विभाग में २००३ पदों की तुलना में महज २४० अधिकारी कार